been formed and it has already visited certain Raj Bhavans. It is to submit its report within a few months...(*Interruptions.*) As regards austerity in other fields I appeal to the Members also; austerity is required not only in Raj Bhavans and the Rashtrapati Bhavan but everywhere.

AN HON. MEMBER: Even in surrender of the salary.

SHRI F. H. MOHSIN: To that effect we have already given a lead. Ministers have already surrendered ten per cent of their salaries and the Deputy Ministers, five per cent towards Bangla Desh fund. We did not lag behind....

MR. SPEAKER: Do not commit yourself too much.

SHRI F. H. MOHSIN: Mr. Sarjoo Pandey said that the Governor should be changed. I do not think that the Governor is acting on the advice of Congress (O) as he said. We expect that all decisions should be taken by the Governors in the best interest of the administration of the State. He should not discriminate between parties and parties but go on doing whatever he thinks to be in the best interest of the State..(*Interruptions*) I do not know about the Gujarat Governor. If he has done like that I would say that it is incorrect to encourage one party and discourage the other.

There was the point about the consultative committee. Though the Government wanted to call meetings of consultative committees quite often, it was not possible because the Prime Minister being the Home Minister has to preside over such meetings and she could not find time. Yet we have been able to call meetings of all the States. You are aware that four States are under the President's rule and already one round is over. We shall make efforts to see that consultative committees meet quite often and consider legislative measures. I should inform Members that these committees are particularly intended to consider legislative measures though they are not barred from discussing policy matters in the interest of administration. Whenever such a need arises, efforts will be made to call a consultative meeting. I think I have met all the points and I would appeal to the House to accept the resolution.

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation issued by the President on the 13th May, 1971, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Gujarat, for a further period of six months with effect from the 21st December, 1971."

The motion was adopted.

16.55 hrs.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: PROCLAMATION IN RESPECT OF THE STATE OF PUNJAB

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): I beg to move:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 15th June, 1971 in respect of Punjab, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 5th February, 1972."

This Resolution is the same as the one which we have just passed. The Proclamation under article 356 of the Constitution in relation to the State of Punjab was issued on 15th July, 1971. It was approved by the Rajya Sabha on 22nd June, and the Lok Sabha on 5th August, 1971. In

[Shri F. H. Mohsin]

accordance with clause (4) of article 356 the Proclamation will remain in force till 4th February, 1972 unless it is extended by the two Houses of Parliament. As I have already stated, in this State also, the revision of the electoral rolls has been started, and has not been concluded. It is to be concluded shortly, but it is not possible to hold the elections before 4th February, 1972. After the proclamation of the Emergency, I do not know whether we would be able to hold the elections in February So, I have come before the House for extension of the Proclamation by six months from 5th February, 1972.

MR. SPEAKER: Resolution moved:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 15th June, 1971 in respect of Punjab, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 5th February, 1972."

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) · स्पीकर साहब, मुझे इस बात पर ज्यादा कुछ नही कहना है। मैं एक ही दरख्वास्त करना चाहता हू। आजकल हम एमरजेंसी मे से गुजर रहे हैं। पंजाब एक बार्डर स्टेट है। आज अगर सब से ज्यादा लड़ाई हो रही है तो उस जगह हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन जो वहां आपने दिया हुआ है उसको आप जरा खींचिये, उसको कहिये, गवर्नर और दूसरे लोगों को कहिये कि जा कर लोगो का मारेल ऊंचा करें। लोगों के प्रति उनकी क्या जिम्मेवारी है, इसका ज्ञान उनको कराइयें। इंटेरिम रिलीफ का क्या हुआ, उसमें मैं पड़ना नहीं चाहता। लोगों के साथ जो वादे किये गए थे, जिन की अभी भी तीन दिन की तनख्वाह बकाया है, उस में भी मैं जाना नहीं चाहता। इंटेरिम रिलीफ के बारे मे सोचा नहीं जा रहा है। और भी जो निहायत जरूरी बातें हैं उन पर हम जोर नहीं देंगे। एक कमिशन मुकर्रर हुआ है उस पार्टी के खिलाफ जिसकी पहले वहां सरकार थी। कमिशन मे वह जिम्मेदारी उन लोगो पर डाल दी है जिन्होंने एलीगेशन लगाए थे। गवर्नमेंट को, चाहिए कि इस बात की जांच कराये। लोगों को मौका दिया जाए कि उनके खिलाफ जितने भी केस हैं जिन पर उनको अपनी सफाई पेश करने का मौका नहीं मिला, उनको पूरा मौका दिया जाए।

नेह नजर आया जांच के बाद तभी तो उसने कमीशन की स्थापना की। लेकिन वहां की जो सरकार है वह कहती है कि हम इसके लिए कतई तैयार नहीं हैं, वह जिम्मेवारी उन लोगों की है जिन्होंने एलीगेशन लगाए थे कि वे उनको साबित करें। मैं समझता हू कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका सारा खर्चा बरदाश्त करे और सारी चीजें बरदाश्त करे। उसकी तरफ ध्यान देना निहायत जरूरी है। लेकिन चूंकि एमरजेंसी आ गई है इस वास्ते मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। वहां की सरकारी मशीनरी को आप गीयर अप करे। सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर लगाने की जरूरत है कि कहीं कोई खराबी वह पैदा होने न दें। जितनी भी चीजें पीछे हुई हैं, वे दुबारा नही होनी चाहिये। उनको सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिये। ऐसा नही होना चाहिये कि यहां से एक आर्डर कर दें कि हम को यह करना है, वह करना है। इससे बात नही बनेगी। उन से आप कहें कि सारी एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर लग जाए कि लोगो मे जागृति पैदा करे, उन का मारेल ऊंचा उठाये। गवर्नर साहब मूव करें। खुद भी मूव करें। तथा दूसरे लोगो को भी मूव करने के लिए कहे। कागजों पर सिर्फ दस्तखत करने से काम नही चलेगा। सबसे जरूरी चीज यह है कि एक नेशन की तरह से हम काम करे, एक आदमी होकर खड़े हो और पाकिस्तान ने जितना एग्रेशन किया है, उसको हम खत्म करें। उसको पीछे हटाये और इस मे जो वहा की एडमिनिस्ट्रेशन है, मदद करे। सारी जनता को, सारे हिन्दुस्तान को एक आदमी की तरह प्राइम मिनिस्टर के पीछे हमें खड़े करना है। इसके वास्ते वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी कम नही है। आज वहां जंग हो रही है। आज चंडीगढ़ मे बैठ कर फैसले नही हो सकते हैं। एक एक जिले में जाकर एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने की जरूरत है और फौजी तौर पर सिविल डिफेंस के लिए लोगों को तैयार करने की जरूरत है। इस काम में वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी कम नहीं है और उसको गीयर अप करने की जरूरत है।

17-00 hrs.

छः महीने के लिए आप वहां राष्ट्रपति का शासन एक्सटेंड तो जरूर कर दें लेकिन अगर आप ऐसे आदमी वहां भेजेंगे जो नई जिम्मेदारियां आयद हुई हैं उनको

विश्वास न पाएं तो एक्सटेंड करने की इसको क्या जरूरत है। आप वहां अच्छे आदमी भेजें जो जा कर काम करें। हम सब मैम्बर पार्लियामेंट कल मीट करेंगे। हम लोग भी जाएंगे और लोगों के सहयोग को ऊंचा उठायेंगे। और भी जो काम करने की जरूरत है, उसको करेंगे। लेकिन वहां की सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको भी वहां की सरकार समझे। जितनी जल्दी यह काम हो उतना ही अच्छा होगा।

मुझे खुशी है कि हमारी फौजों ने हमला-आवर को कवटेन किया हुआ है और वे उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। लेकिन फौजों के लिए सब किस्म का सामान वगैरह पहुंचाने की पाइप लाइन को पूरी तरह जारी रखने का इन्तजाम भी किया जाना चाहिये। यह ठीक है कि हमारी फौजें बहादुर हैं और पंजाब और बार्डर के दूसरे लोग भी बहादुर हैं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से यह इस्तदुआ करूंगा कि वह एडमिनिस्ट्रेशन को पुल अप करें। मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करने का यही मौका है, क्योंकि बाद में तो वहां पर डेमोक्रेटिक सेट-अप आ जायेगा। अगर प्रेसिडेंट्स रूल के मातहत यही काम कर के दिखाया जाये, तो बहुत अच्छा होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में राष्ट्रपति-शासन को और छः महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव इस सदन में विचाराधीन है। अभी पाकिस्तान ने खास तौर से पंजाब के क्षेत्र को ही अपने हमले का निशाना बनाया है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता यह थी कि वहां पर कोई लोकप्रिय सरकार होती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार होती। जहां तक वहां चुनाव कराने का सम्बन्ध है, संकट कालीन स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि फिलहाल वहां चुनाव कराना सम्भव नहीं होगा। इसलिये यह बहुत जरूरी है कि वहां का शासन ऐसी नीतियां अपनाये, जिस से उस सीमावर्ती राज्य के लोग संतुष्ट रहें, उन का हौसला बुलन्द रहे और वे मजबूती के साथ दुश्मन का मुकाबला कर सकें।

बदकिस्मती से इस समय वहां के शासक वे लोग हैं, जो नौकरशाह कहे जाते हैं। आम जनता के प्रति नौकरशाहों का क्या रवैया होता है, यह सर्व-विदित है। मुझे इस बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन खास तौर से आज की स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि वे नौकरशाह अपनी नौकरशाही प्रवृत्ति को छोड़ कर वहां के किसानों, मजदूरों, गरीबों और मध्यमवर्गीय कर्मचारियों के सहयोग से काम करें, ताकि उस प्रदेश के सभी लोग मिल कर पाकिस्तानी हमले का मुकाबला करें और अपने देश की एकता और आजादी को बचा सकें।

कुछ दिनों पहले वहां की पुलिस ने जिस तरह का नंगा नाच किया, दो निर्दोष छात्रों की हत्या की, अगर उस को हिटलरी तरीका कहा जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वहां किसानों, मजदूरों और खास तौर से हमारे दल के लोगों पर इस तरह से हमले किये गये, जिन को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कम से कम एक जनतांत्रिक हुकूमत में इस प्रकार के हमलों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन घटनाओं के बारे में पूरी जांच की जाये और जो अफसर दोषी पाये जायें, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाये।

वहां के किसानों को अपने विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। वहां पर नये कानून बनाये जाने चाहिए, जिन के तहत गरीबों में जमीन का बटवारा किया जाये, ताकि बेजमीन लोग यह समझें कि यह देश उनका है, उन को अपनी पूरी ताकत से इस देश को बचाना है और साथ ही खेती की उपज को भी बढ़ाना है। बिना खेती की उपज के हम अपने जवानों और देशवासियों को क्या खिला सकेंगे? पंजाब उपज बढ़ाने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान में सब से मशहूर है। इसलिये यह जरूरी है कि हम वहां के खेत-मजदूरों और गरीब किसानों को अपने विश्वास में लें।

वहां के सरकारी कर्मचारी पिछले दिनों बड़ी बहादुरी के साथ अपनी मांगों के लिए लड़ चुके हैं। उन के साथ कुछ वादे भी किये गये थे, लेकिन अभी तक उन को पूरा नहीं किया गया है।

[श्री रामावतार शास्त्री]

ये लोग देशभक्त हैं। ये देश की हिफाजत करना और दुश्मनों के खिलाफ लड़ना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। लेकिन सरकार का भी यह फर्ज है कि वह इन लोगों की तकलीफों को दूर करे और उनकी मांगों को स्वीकार करे, ताकि ये दिल से और संतुष्ट हो कर अपना काम कर सकें।

अकाली मंत्रि-मंडल द्वारा वहां पर क्या क्या गलत काम और भ्रष्टाचार किये गये, इस बारे में बड़ी चर्चा होती रही है। हम चाहते हैं कि उसके बारे में पूरी इनक्वायरी हो, ताकि पंजाब की जनता को मालूम हो सके कि अकाली मंत्रि-मंडल ने वहां की जनता के साथ क्या क्या नाइन्साफियां और अत्याचार किये हैं। वहां की बेकारी की समस्या की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ताकि वहां के नौजवान यह महसूस कर सकें कि आज देश पर जो आफत आई है, उसका मुकाबला करने में उन को भी योगदान करना है। अगर सरकार ने ये सब काम न किये और केवल राष्ट्रपति-शासन की अवधि को बढ़ा दिया, तो जो नुकसान होगा उसकी जवाबदेही से वह बच नहीं सकती है। इसलिए अपने जवाबदेही को निबाहने के लिए सरकार को इन सब कामों को करना होगा, ताकि वहां की जनता एकताबद्ध होकर प्रगति कर सके।

SHRI AMARNATH VIDYALANKAR (Chandigarh): Sir, just as my hon. friend, Shri Darbara Singh, has said the people in the Punjab have always remained in the forefront and they want to remain in the forefront in the struggle. At such a time the administration should show some dynamism. At present the administration or the bureaucracy is not showing that dynamism and it is functioning in the same old way.

We want that not only the government employees but the people should have a sense of participation. The way in which the employees are being dealt with is not the way in which you can create a sense of participation. The previous Akali administration mismanaged and quarrelled with the employees. A certain enquiry was instituted and some employees were suspended. We expected that when Governor's rule was imposed the administration would start on a clean slate but our hopes have been belied. The new administration should have removed all the obstacles and created a sense of participation, a sense of friendship and co-operation among the employees. But that feeling was not created and is not being created. I think it is very much necessary, specially in view of the present situation, that a feeling of satisfaction should be created in the minds of the employees, whose leaders are being prosecuted in the courts. The employees have many grievances. They have not been paid for the strike period and their associations have not been recognised. Since their grievances are not big once they should have been removed and the Governor's rule should have started with a clean slate. We should now create a sense of satisfaction among the employees so that the employees and the administration could work together and they would have a sense of unity and participation in the administration.

I know that certain steps have been taken in the field of civil defence and some councils have been constituted. But there are many people who can contribute a lot but who have not been included in these councils. So, I say that these councils have not been constituted in a proper manner. If the present administration, specially the bureaucracy, cannot work or is not fit to face the present situation, they should be changed. But I will request the Minister that they should be told that at present there cannot be any timid way of administration. There should be some dynamism, a sense of cooperation and they should create that kind of a spirit in the Punjabis. Already the Punjabis are full of that spirit. The administration also should show that

spirit. I feel that the Home Minister will specially pay attention to the employees' grievances and clear the kind of obstacles that the administration has not removed.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह पंजाब मे प्रेसीडेंटस रूल जो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है इसमे मुझे कुछ ज्यादा नही बोलना है। दो तीन बातें जो प्रेसीडेंट रूल अब तक है उस मे हो रही है उन की तरफ मै मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हू। सब से पहली बात यह है कि पुलिस जिस तरह से वहा बर्ताव कर रही है प्रेसीडेंट्स रूल के अन्दर वह कहने के लायक नही है। आज भी आप ने अखबारो मे देखा होगा कि दो आदमियो को पकडा, थाने मे रखा, मैजिस्ट्रेट के सामने तक नही हाजिर किया उसके लिए हाई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ राय दी है कि यह बिलकुल गलत काम पुलिस ने किया और उस ने उन को छोड़ दिया। अभी कुछ दिनो पहले दो स्टूडेंट्स को पुलिस ने मार डाला है। उस के बारे में लोग एन्क्वायरी के लिए गए, जुडीशियल एन्क्वायरी लोग मांग रहे है, आज तक वह बात नही मानी गई है। इस की जुडीशियल एन्क्वायरी होनी चाहिए और यह मालूम होना चाहिए कि यह क्या किया गया, दो नौजवानो की जान क्यो ली गई? इस की एन्क्वायरी अवश्य होनी चाहिए और पब्लिक को मालूम होना चाहिए। यही नही, आम तौर से वहां की पुलिस का जो काम है वह ऐसा है कि क्या कहा जाय? वह समझते है कि सैंया भये कोतवाल अब डर काहे का? वह अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैंने तो देखा बंगाल मे यह हो रहा है कि किसी को पकड कर थाने मे ले जाते है, मारते है, पीटते हैं और फिर जो चाहते हैं वह केस उस के ऊपर लगा देते हैं। नक्सली होने का नाम ले कर उन को पीटा जाता है। जिन की जान भी ली जा रही है उसे नक्सली कह कर, एक्सट्रीमिस्ट कह कर मार डालते हैं और फिर उन का कुछ नहीं होता। मै मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस चीज का वह ख्याल करें।

दूसरी चीज यह है कि वहां पर लैंडलेस पीजेंट्स हैं जिन को कि ईवैकुईज की जमीन तकसीम होनी थी, लेकिन वह जमीन आज तक उन लैंडलैस लोगो को, हरिजनों को नहीं मिली है। इस में बहुत सी धांधलियां हैं। आफिशियल्स वह जमीन अपने नाम कर के और अपने रिश्तेदारो के नाम में कर के रखे हैं। उन हरिजनों को वह जमीन नहीं मिली है जो उस को जोतते हैं, बोते हैं। उन को वहां से भगा दिया जाता है। मैं यह चाहता हू कि एक आल पार्टीज कमेटी उस के लिए होनी चाहिये जो जितनी ईवैकुईज लैंड है उस मे जो किसान उस को जोत बो रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, उन को वह जमीन पांच एकड़ के हिसाब से तकसीम करे। इसके लिए एक आल पार्टी कमेटी होनी चाहिये।

तीसरी बात मुझे इन्टेरिम रिलीफ के बारे मे कहनी है। चंडीगढ़ मे इंटेरिम रिलीफ कुछ लोगो को सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट्स के मुताबिक दी जा रही है। मगर पंजाब के एम्प्लाइज के लिए वह चीज नहीं मानी गई है। इस का कारण मैं कुछ समझ नही पाया। जब प्रेजीडेन्ट्स रूल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस बोर्डर स्टेट के एम्प्लाईज को देखने की कि उन को यह मिले।

चौथी चीज मुझे यह कहनी है कि बार्डर इलाके में बहुत सी जगह पर किसानो को हटाना पड़ा है जो वहा अपनी फसल भी नही बो सकते हैं तो ऐसे किसानों को कम से कम कम्पेन्सेशन या मुआवजा कुछ न कुछ जरूर मिलना चाहिए। जो बोर्डर का इलाका है वहा के जो किसान हैं जिन को हट जाना पडा है उन को देखना होगा। यह काम भी सरकार को करना है।

आखिरी बात मै अकाली आन्दोलन जो चल रहा है उस के बारे मे कहना चाहता हू। आज एमर्जेंसी डिक्लेयर हुई है और पंजाब हमारा बार्डर स्टेट है, उस के अन्दर हमे यूनिटी लाने की कोशिश करनी है। यह जो अकाली आन्दोलन चल रहा है इस मे कम्यूनल चीज आगे आ रही है और जनता का दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है। सवाल यही था कि वह यही मांग कर रहे थे कि एलेक्टेड रेप्रेजेन्टेटिव को मानें, उस के लिए कोई आफिशियल एनाउसमेंट अब तक नहीं हुआ। आफिशियल एनाउंसमेंट हो जाता कि हम यह करेंगे, गवर्नमेंट यह करेगी तो यह आन्दोलन कब का खत्म हो जाता। इस तरह की बात चलने से कम्युनल टेंशन

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

बढ़ रहा है और वातावरण खराब हो रहा है। यह चीज नहीं होनी चाहिए। यही मुझे कहना है।

श्री सतपाल कपूर (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, आज की हालत में और स्पैशली जब एमर्जेंसी हम डिक्लेयर कर चुके हैं, हम पर जंग थोप दी गई है, मैं पंजाब के लोगों की तरफ से इस हाउस को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी कुर्बानी पंजाबियों को करनी चाहिये, जितनी आप उनसे तवक्को कर रहे हैं, उस से ज्यादा पंजाब के लोग कुर्बानी देंगे। पंजाब का हर इंडिविजुअल बोर्डर पर जा कर लड़ने के लिए तैयार है। जंग आज शुरू हुई है, पाकिस्तान ने जंग आज हम पर थोपी है लेकिन पिछले 9 महीनों से पंजाब में जंग के हालात बने हुए हैं। हम उस का मुकाबला कर रहे हैं और पंजाब के नौजवान, पंजाब के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि कब रावलपिंडी और लाहौर पहुंचें और इस मुकाबिले में पूरा यकीन है पंजाब को कि रावलपिंडी और लाहौर में जा कर हम जंग लड़ेंगे और वहां पर कब्जा करेंगे।

जहां तक हमारे दोस्त दरबारा सिंह जी और विधानकार जी ने जिन बातों की चर्चा की है मैं उस के साथ पूरा इत्तफाक करता हूं। जहां पंजाब के लोग बहादुर हैं, वहां पंजाब के लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, जहां पंजाब के लोग ज्यादा पैदावार करने के लिए मशहूर हैं, कन्ज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में जहां वह राष्ट्र की रहनुमाई कर रहे हैं, वहां आज उसकी नुमाइन्दगी पूरी तरह पर आप की ब्यूरोक्रेसी पंजाब में नहीं कर रही है। वहां के लोगों के साथ, वहां के मुलाजमीन के साथ, वहां के बिजनेसमैन के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, माफ कीजिए, आज की हालात में वह चर्चा हम कर नहीं सकते। जिस तरह पंजाब में आप ने पुलिस राज बना रखा है, गरीब किसानों को पहले वह पकड़ते हैं और बाद में गोली मार कर कहते हैं कि वह तो मुकाबले में मारे गये, किस तरह से दो स्टूडेन्ट्स को गोली से उड़ा दिया और बाद में कह दिया कि वह बदमाश थे। मैं मान सकता हूं कि किसी का कैरेक्टर खराब हो, कोई बदमाश हो, कोई चोर हो, लेकिन किसी पुलिस वाले को आज के राज में उसे इस तरह से गोली से उड़ा देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उस की एन्क्वायरी होनी चाहिए।

जहां तक सरकारी मुलाजमीन का सवाल है, उन के साथ वादे किए, सरकार ने वादे किए लेकिन आज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पंजाब के अफसरान इस पार्लियामेंट की नुमाइन्दगी नहीं कर रहे हैं। पंजाब में प्रेजीडेंट्स रूल है तो वह प्रेसीडेंट्स रूल इस सरकार के अंडर में चल रहा है और यह सरकार किसकी है? लोगों की सरकार है और लोगों की सरकार की नुमाइन्दगी करने वाले अफसरान वहां ऐंटी पीपुल काम कर रहे हैं। आप को उस से सबक लेना चाहिए। आप को उन्हें रोकना चाहिए, उन्हें बान्धना चाहिए। आप ने जो यहां से ऐडवाइजर भेजे हैं उन की समझ में नहीं आ रहा है पंजाब क्या है? पंजाब एक जंग लड़ने वाला इलाका है। आप उस पर डिपेंड कर रहे हैं तो उस के ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारिए। अगर रखना है तो अच्छे अफसरान वहां रखिए। मैं तो यह चाहूंगा कि आप ने जो अफसरान यहां से भेजे हैं उनको आप वापस ले लीजिए, हम पंजाबी खुद ही पाकिस्तान वालों से निपट लेंगे। आप अपने जो नुमाइन्दे भेजते हैं उन की कुछ समझ में नहीं आता कि पंजाब क्या है। मैं बहुत तफसील से कहना चाहता था लेकिन आज की हालत में कह नहीं सकता। इसलिए आप से प्रार्थना करता हूं कि देश की और पंजाब की हालत को समझते हुए मैं पंजाब से जिस किस्म का काम लेना चाहते हैं उसके लिए लोग तैयार हैं, उस के लिए आप तैयार होइए।

SHRI F. H. MOHSIN: Mr. Speaker, Sir, I am really thankful to the Members of this House for giving very valuable suggestions.

Almost every Member has stressed the strategic importance that Punjab has got. Really speaking, Punjab has got very great importance in the present Emergency. It is a border State facing more risks and also naked aggression by Pakistan. Since yesterday night we have been hearing how a naked aggression has been committed on the various towns of Punjab. I must really congratulate the Punjabis for their bravery. I remember how they withstood the aggression that was committed even in 1965 and the courage they are even showing to-day.

I quite remember an incident, especially in Amritsar and Ambala, where the enemy planes had come in 1965 and when a dog-fight was going on over the city of Amritsar, the people were not afraid. They came out of their houses to watch the fight that was going on between the war planes of Pakistan and our planes So, I have no doubt that the Punjabis are very brave and they will not be hesitant to save our motherland from any aggression of this sort

At this hour it is quite natural that some of the traders and black-marketeers would like to take advantage of such a situation and would start hoarding essential commodities So stress was laid by various Members of the House to see that the prices do not rise We have already passed the Defence of India Act I do think that that will take care of such black-marketeers who engage themselves in hoarding

SHRI DARBARA SINGH Please gear up the machinery there

SHRI F H MOHSIN I must also admit that the suggestions that were given by Sardar Darbara Singh are very valid The administrative machinery should gear up to the need of the hour and see that the grievances of the people are met It is no use if they adopt a bureaucratic attitude They must keep in touch with the masses, try to understand the difficulties of the masses and try to redress them

I am surprised to hear some complaints made by some hon Members of this House about the attitude of some officers If it is really so, I am very much pained to hear that as especially in the Emergency everybody including the officers should gear up the administration and see that the people are attended to in every field of activity and also encourage them to participate more and more in the war efforts at such a critical hour.

I am very much thankful to Mr. Amarnath Vidyalankar and Mr. Ismail and Mr. Sat Pal Kapur as also to Mr. Ramavatar Shastri for their very valuable suggestions. Some points were made about charges against the Ministers in the former Ministry Great stress was laid on corruption. The drive against corruption was intensified. About 83 Government employees were caught red-handed while accepting bribes and they were also proceeded against. In all 86 cases have been registered. Against the Ministers in the former Ministries a number of memoranda alleging abuses of power and other malpractices against the members of the former Governments and Government servants were screened and you will be glad to know that there is a commission of inquiry appointed by the Government of India in this connection and the inquiry is proceeding.

SHRI DARBARA SINGH : Is the Government going to take up that matter because the allegations have been *prima facie* proved ?

SHRI F H MOHSIN That is upto the Commission to see whether the cases are proved or not The Commission will take care of that

श्री सत्यपाल कपूर : कमीशन में आप पार्टी होंगे या नहीं, या इन्डिविजुअल ही पार्टी होंगे ?

SHRI F H MOHSIN Many suggestions have come from the hon. Members and the Government will seriously look into them

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) ऐसा कमीशन हरियाणा में भी बनायेंगे या नहीं, वह तो बतलाइए।

SHRI F H. MOHSIN At present we are discussing about Punjab. So, I cannot make a statement about Haryana.

Shri Mohammad Ismail had raised a question about the Government employees.

[Shri F. H.Mohsin]

Relief has been given to the employees of the State Government, and the enhancement of the rate of dearness allowance also has been given with effect from 1st July, 1971, and the increases thus amounted to Rs. 6 to Rs. 11 per month. This has benefited about 1,60,000 employees, and it costs the exchequer Rs. 1.41 crores per year.

It is true that Punjab had to suffer even on account of floods. The monsoon caused unusual floods in Patiala, Gurdaspur and Amritsar, Rupar and Jullundur districts, and steps were taken to relieve the distress. Immediate action was taken to evacuate the marooned persons. A sum of Rs. 23.13 lakhs in addition to the normal budget was also kept at the disposal of the deputy commissioner to give relief.

These were some of the points raised by various Members, and all the suggestions made by hon. Members will be kept in mind.

MR. SPEAKER: What advice is he giving to the Akalis ?

SHRI F. H. MOHSIN: In view of the present situation of emergency, I appeal to the Sikh community...

SOM EHON. MEMBERS: No, no....

SHRI F. H. MOHSIN: I am sorry....

SHRI DARBARA SINGH: We object to this remark. Let the hon. Minister hear me. There is only one class of people from among the Sikhs, that is called the Akalis, who are in the habit of doing all these things. Why should he talk about the whole Sikh community....

SHRI F. H. MOHSIN: I have not completed my sentence yet. I would appeal to the members of the Sikh community to persuade the Akalis, and I woluld appeal to the other communities also to persuade the Akalis to withdraw the agitation, in view of the present emergency. I stand corrected again. It is only a section of the Akalis who are doing it. So, I would appeal to them to withdraw their agitation in the face of the emergency that we are facing today.

MR. SPEAKER: I hope they will care for his advice. They are in a mood to care for his advice now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): They have already called off their agitation.

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 15th June, 1971 in respect of Punjab, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 5th February, 1972."

The motion was adopted.

17.29 hrs.

RESOLUTION *RE*: PROCLAMATION IN RESPECT OF THE STATE OF WEST BENGAL

THE DEPUTY-MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): I beg to move:

"That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 29th June, 1971, in respect of West Bengal, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 29th January, 1972."

This resolution is on the same lines as the earlier ones, and now this is in respect of West Bengal. This seeks to extend the Proclamation in relation to the State of West Bengal for a further period of six